DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS-------- THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI SATURDAY, OCTOBER 8, 2022 -DATED----------

Walk In The Woods: Sanjay Van Calls Nature Lovers With Workshops, Tree Census & More

Sidhartha.Roy@timesgroup.com

New Delhi: Delhi Development Authority (DDA), which organised a dragonfly festival at Sanjay Van in south Delhi last month, plans to conduct more such activities as part of 'Learning with Nature' initiative over the next two and a half months.

The activities, to be organised in the forest in collaboration with WWF India, are part of the authority's aim to promote the partnership of citizens in preserving city forests and to encourage nature-based learning, especially among children. The activities will include workshops, butterfly walk, photography workshop, tree census, bird census, nature trail and clean-up drives.

Spread over around 784 acres, Sanjay Van with a rich diversity of flora and fauna is home to a number of birds, reptiles, butterflies, mammals, etc., an official said.

On October 16, Sunday, a workshop on butterflies will be held, followed by a walk led by an expert to observe different species of butterflies. On October 24, DDA will organise a dragonfly 'biolblitz'— a census to observe the different species of dragonflies and damselflies found in the notified reserved forest. The last activity of this month will witness a clean-up drive with a group of volunteers.

A butterfly walk, which will be led by an expert, to observe different species of butterflies found in the area will be held in November. A photography workshop on how to capture nature and biodiversity will be conducted by an expert on November 12.

A tree walk with an expert will be conducted on November 26, which will be followed by a census to observe and take photographs of different tree barks and species. Another clean-up drive by volunteers will be carried out the next day.

A bird census will be held on all weekends in December to observe different species of birds at a time when migratory birds are likely to arrive in the area. On December 10, a 'forest bathing walk', a nature trail by an expert, will be held for visitors to use their senses in understanding and observing nature. On December 17, a workshop on birds will be held, followed by a bird walk the next day.

Most of the nature activities will be conducted with a limited number of participants. The entry will be by registration on a first-come, first-served basis. The registrations will open two weeks before the respective events.

CLOSER TO NATURE

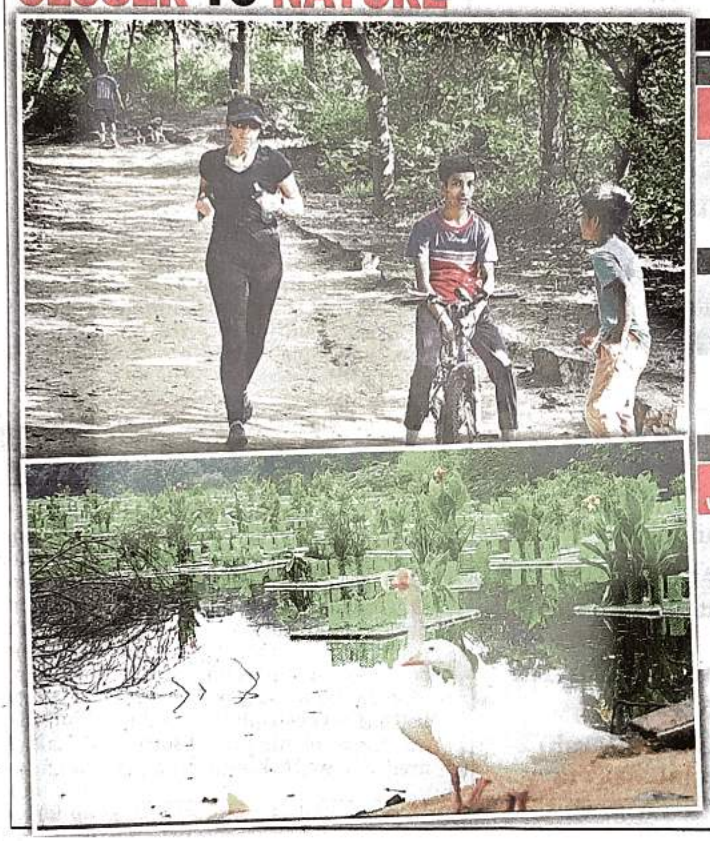

CALENDAR OF NATURE ACTIVITIES AT SANJAY VAN

Date	Activity	Maximum Participants
OCTOBER		
16	Workshop on butterflies	25
24	Dragonfly 'bioblitz' (census)	Open to public
29	Volunteer clean-up drive	30
NOVEMBER		
12	Butterfly walk	25
19	Workshop on nature photography	25
26	Bark census (census of tree barks and species found on it)	30
27	Volunteer clean-up drive	30
DECEMBER		
all weekends	bird census	Open to public
10	Forest 'Bathing Walk' (observing nature through all senses during nature trail)	Open to public
17	Workshop on butterflies	25
18	Bird walk (arrival of migratory birds)	30

784 ACRES Total area of Sanjay Van

150 Species of birds found in the city forest

5 Number of waterbodies in the area

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
SATURDAY, OCTOBER 8, 2022

NEWSPAPERS---DATED-----

दैनिक जागरण नई दिल्ली, 9 अक्टूबर, 2022

1,110 ghats, ₹25-crore budget: Govt plans in place for Chhath

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: For over 40 lakh Poorvanchalis who have made Delhi their home, the Delhi government has decided to set up 1,100 ghats – temporary and permanent – along the Yamuna, near old waterbodies and in several MCD and DDA parks to ensure the devotees do not have to travel much to offer prayers on Chhath Puja.

As the number of Poorvanchalis – the natives of eastern Uttar Pradesh and Bihar – has increased in Delhi in the past decade or so, the festival, too, has gained popularity and is celebrated with fervour. Apart from readying the ghats for offering prayers, the Delhi government makes several arrangements to ensure the devotees do not face inconvenience.

Revenue minister Kailash Gahlot held a review meeting on Friday on the preparedness of Chhath Puja in Delhi. The meeting was attended by divisional commissioner KR Meena and district magistrates of all 11 districts of the capital. Revenue department is the nodal agency for making arrangements for the celebration of Chhath Puja in a safe, secure and eco-friendly manner with full festivity.

According to officials, the department will make arrangements for tents, chairs, tables, lighting, sound system, CCTV, LED screens and power backup at all the sites. The departments will also be in close coordination with the officials of irrigation and flood control and Delhi Jal Board for arranging clean water, health department for primary health services and deployment of ambulances, DUSIB for mobile toilet vans and Delhi Police and civil defence to provide safety and security, traffic police and with civic agencies for sanitation and cleanliness.

Gahlot said the number of puja sites has increased from just 69 in 2014 to 1,100 and the budget has also gone up by 10 times from Rs 2.5 crore in 2014 to Rs 25 crore this year. "The arrangements this year will be unprecedented. Apart from increasing the number of ghats, we have also ensured there are proper facilities for the devotees' family members at the puja venues," Gahlot said.

जी-20 शिखर सम्मेलन के लिए तैयारी, 375 स्थानों पर लगाई जाएगी फुलवारी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : जी-20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर उपराज्यपाल वीके सक्सेना के दिशानिर्देशों के तहत निगम ने विभिन्न स्थानों पर फूलों वाले पौधे लगाने की तैयारी शुरू कर दी है।, ताकि दिल्ली सुंदर दिखे और फूलों की खुशबू से महके। इसके लिए सोमवार से विभिन्न स्थानों पर निगम ने पौधों के बीजारोपण का कार्य शुरू कराया है। पौधे तैयार होने के बाद इन्हें उचित स्थानों पर रोपा जाएगा। दिल्ली नगर निगम ने इसके लिए फ्लाईओवर से लेकर रिहायशी इलाकों, चौराहो, सेंट्रल वर्ज और फुटपाथ के किनारे व मंनोरंजक स्थलों के करीब लगाया जाएगा।

उपराज्यापल वीके सक्सेना दिल्ली नगर निगम समेत, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी), दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीयू), लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए थे कि जी-20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर फूल वाले पौधे लगाए। एनडीएमसी पहले से इस तरह के प्रयोग लुटियंस दिल्ली की सड़कों पर करता है, लेकिन उपराज्यपाल के निर्देश के बाद एनडीएमसी ने भी नए प्रयोग करने की तैयारी की है, जिसमें कर्तव्य पथ पर दिल की आकृति में भी पौधे लगाए जाएंगे।

नगर निगम के एक पार्क में शुरू किया गया फूल वाले पौधों का बीजारोपण। क्यारी बना रहा निगम का कर्मचारी • सौजन्य : नगर निगम

पौधे रोपने के लिए निगम के 12 जोन में चिह्नित स्थान
16 फ्लाइओवर
261 कालोनी के पार्क
27 बाजारों में पार्क
62 मुख्य सड़कों पर पार्क
नौ चौराहे

चिह्नित फ्लाईओवर : नेहरू प्लेस, सराय काले खां, लाजपत नगर, साउथ एक्स, कालकाजी, सीलमपुर, गोकुलपुरी और रानी झांसी फ्लाईओवर, शालीमार पार्क, प्रियदर्शिनी पार्क, टीचर पार्क, निमड़ी कालोनी आदि।

फूल के पौधे रोपे जा रहे : गजोनिया, वर्बाना, कोरियोप्सिस, एलिसम, कैलेंडुला, एस्टर, नेमेशिया, पेटुनिया, कार्न फ्लावर, डहलिया आदि।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS । संडे नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । 9 अक्टूबर 2022 TED----------

ये प्रेम पत्र नहीं, एक अभिभावक के तौर पर मेरा कर्तव्य पत्र है : एलजी

एलजी ने सीएम को फिर लिखा पत्र, मर्यादा की सीमाएं लांघने का आरोप लगाया

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच खटास कम होने का नाम नहीं ले रही। उपराज्यपाल के पत्रों को 'प्रेम पत्र' बताए जाने के बाद अब उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री को छह पेज का पत्र लिखकर उन पर और उनके सहयोगियों पर मर्यादा की सीमाएं लांघने और संवैधानिक कर्तव्यों से भागने का आरोप लगाया है। उपराज्यपाल ने अपने पत्र में एक्साइज पॉलिसी पर जांच समेत सभी विवादित मुद्दों का जिक्र करते हुए पूछा है कि इनके बारे में जांच का आदेश देकर उन्होंने कौन-सी गलती की है? एलजी ने कहा है कि यह उनका 'प्रेम पत्र' नहीं, बल्कि 'कर्तव्य पत्र' है।

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के पत्रों को तथ्यहीन और भ्रामक बताते हुए कहा कि उन्होंने उपराज्यपाल के तौर पर दिल्ली के अभिभावक के रूप में जब भी मामले उठाए, उनका जवाब नहीं दिया गया। उल्टा तथ्यहीन और व्यक्तिगत आक्षेप लगाए गए। उपराज्यपाल ने पत्र में यह भी दावा किया है कि उन्होंने जो भी मुद्दे उठाए, वे दिल्ली के लोगों की भलाई से जुड़े हैं। यही नहीं, वे सिर्फ दिल्ली सरकार के ही नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस, डीडीए और नगर निगम से जुड़े इस तरह के मामलों की जांच कराते हैं। हाल ही में नगर निगम के टोल टैक्सों में गड़बड़ी का जिक्र करते हुए उपराज्यपाल ने कहा है कि जब 'आप' नेताओं ने ये मामला उठाया तो उस पर भी उन्होंने डिटेल रिपोर्ट तलब की है।

File Photo

एलजी ने 6 पन्नों के पत्र में 11 मुद्दों का जिक्र किया, पूछा- जांच का आदेश देकर कौन सी गलती की?

उपराज्यपाल ने अपने पत्र में एक्साइज के अलावा उन 11 मुद्दों का जिक्र किया है, जो उन्होंने पद संभालने के बाद मुख्यमंत्री को लिखे। उपराज्यपाल ने कहा कि जब उन्होंने फाइलों पर मुख्यमंत्री के साइन का मामला उठाया तो उसके बाद मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर से फाइलें आने लगी हैं। इसी तरह से जब उन्होंने सीएजी की रिपोर्ट का मामला उठाया तो विधानसभा का सत्र बुलाकर एक साथ चार वर्ष की सीएजी रिपोर्ट पेश कर दीं। बिजली सब्सिडी के मामले का जिक्र करते हुए उपराज्यपाल ने लिखा है कि ये मामला डीईआरसी ने 2018 में उठाया था। उन्होंने पेड़ों की कटाई का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने इस मामले में रुकी फाइलों का मामला इसलिए उठाया, क्योंकि इससे कई प्रोजेक्ट लेट हो रहे थे। एलजी ने अंत में लिखा कि मुझे आशा है कि मेरे इस संदेश को आप सही मायने में, दिल्ली के अभिभावक से प्राप्त 'कर्तव्य पत्र', जिसे आप 'प्रेम पत्र' की संज्ञा दे रहे हैं, के रूप में स्वीकार करेंगे।

LG के जरिए BJP दिल्ली वालों की जिंदगी तबाह करने पर तुली : सीएम

■ **विस, नई दिल्ली:** उपराज्यपाल ने चिट्ठी लिखकर मुख्यमंत्री केजरीवाल और उनके मंत्रियों पर जिम्मेदारी और संवैधानिक कर्तव्यों से भागने का आरोप लगाया है। इस के जवाब में केजरीवाल ने उपराज्यपाल पर तंज करते हुए ट्वीट किया, 'आज एक और लव लेटर आया है।' इसके कुछ देर बाद मुख्यमंत्री ने अगला ट्वीट करते हुए लिखा कि बीजेपी, एलजी के जरिए दिल्ली के लोगों की जिंदगी तबाह करने पर तुली है। रोज ये लोग किसी न किसी बात पर बखेड़ा करते हैं। मैं दिल्ली वालों को भरोसा दिलाता हूं, जब तक ये बेटा जिंदा है, चिंता मत करना। आपका बाल भी बांका नहीं होने दूंगा।

मुख्यमंत्री के ट्वीट को ही रिट्वीट करते हुए उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने लिखा कि हर रोज आप का गुजरात में जनाधार मजबूत होता है और हर रोज दिल्ली में एक नई फर्जी जांच शुरू होती है। इनकी अरविंद केजरीवाल को रोकने की साजिशों से हर व्यक्ति वाकिफ है। ये चाहे जो कर लें, न तो दिल्ली में जनता के हित में हो रहे काम रुकेंगे, न गुजरात में आप की लहर।

। नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । शनिवार, 8 अक्टूबर 2022

फैसले का स्वागत

■ **विस, नई दिल्ली :** कांग्रेस ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले का स्वागत किया है, जिसमें मुंडका की सीवर लाइन में ड्यूटी पर दो लोगों की मौत मामले में संज्ञान लेकर परिजनों को 10-10 लाख रुपए का उचित मुआवजा और अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने का आदेश जारी किया है। साथ ही डीडीए को 30 दिनों में परिजनों को मुआवजा और अनुकंपा पर नौकरी देने के आदेश दिया है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NEW DELHI
SUNDAY
OCTOBER 09, 2022

NAME OF NEWSPAPERS---- Sunday Hindustan Times

Govt shirking responsibility, says LG; another love letter, retorts CM

Paras Singh
paras@hindustantimes.com

NEW DELHI: The unabated war of words between the Delhi lieutenant governor and the state government further intensified on Saturday with LG VK Saxena writing a scathing letter to Delhi chief minister Arvind Kejriwal accusing his government of "running away from constitutional duties" and a member of his party of "crossing all boundaries of propriety" even as the AAP chief termed it "another love letter" from the LG and an attempt by the Centre to disrupt the lives of citizens of Delhi.

> I hope that you will accept this message of mine in the true sense as a 'duty letter' received from the guardian of Delhi, which you are calling 'love letter'.
>
> **VK SAXENA,** Delhi lieutenant governor

> Have received yet another love letter today. BJP is trying to destroy the lives of people of Delhi through LG. These people create one issue or another every day.
>
> **ARVIND KEJRIWAL,** Delhi chief minister

The letter comes in the backdrop of several probes that the LG has ordered against the Delhi government, attracting sharp reactions from the top AAP leadership, which has accused the LG of acting at the behest of the BJP-led central government.

In a six-page letter, dated October 7, Saxena said, "I hope that you will accept this message of mine in the true sense as a 'duty letter' received from the guardian of Delhi, which you are calling 'love letter'..." — a direct swipe at a tweet by Kejriwal on Thursday in which he had said that even his wife has not written him as many love letters as the LG has sent him in the past six months.

In separate tweets in Hindi, Kejriwal said, "Even my wife does not scold me as much as LG sahib scolds me every day."

"In the last six months, my wife has not written me as many love letters as LG Sahib has written to me. LG sahib, chill a bit. And also tell your super boss to chill," the chief minister had said.

Citing 11 interventions and probes that he has ordered against the AAP government, the LG said, "Your government is running on the basis of advertisements and speeches. When I, while discharging my constitutional responsibilities, made you aware of these shortcomings and requested you to redress them, you and your colleagues not only misled the people, but also made baseless personal allegations. Take cognizance and reference of Manish Sisodia's baseless, misleading and nonsensical statements."

"I would like to remind you that the issues that were conveyed to you in the letter constituted the feelings of all the common citizens of Delhi and the issues were related to administration. I, or the people of Delhi, have not yet received any satisfactory reply from you on those matters."

Chief minister Kejriwal responded to the latest letter in a tweet, "Have received yet another love letter today." And added, in another tweet, "BJP is trying to destroy the lives of people of Delhi through LG. These people create one issue or another every day. I want to assure the people of Delhi that until their son [Kejriwal] is alive, you need not worry. I will not let anything bad happen to you."

Last Tuesday, deputy chief minister Manish Sisodia wrote to the LG and accused him of ordering "illegal and unconstitutional" probes against the Delhi government's decisions. "Of all the investigations you have ordered so far, nothing came out in even a single one of them...Such bogus and frivolous scams serve no one. It only wastes the time of all the departments and shatters the morale of all the officers," said Sisodia.

Responding to allegations levelled by Sisodia in a second letter on Wednesday, in which the deputy CM asked the LG as to why he had not ordered probe into the "toll tax collection scam by MCD", the LG said that he has been completely impartial in discharging his constitutional duties.

"I have tried to highlight lapses and acted against corruption in all department including DDA, MCD and Delhi Police. I had sought detailed reports on allegations related to toll tax collection and the factual reports show that MCD has revoked the contract of the private agency and legal action is being undertaken for recovery," Saxena said.

In his letter, Saxena also cited several cases of defamation filed against AAP leaders by opposition figures,

Sisodia on Thursday linked the "daily attacks on the AAP government" to the rising popularity of his party in Gujarat. "The mandate for AAP is growing in Gujarat ever day, just as a new inquiry is set up in Delhi. People understand their [BJP's] efforts to stop Kejriwal. No matter what they do, neither the development works in Delhi will stop, nor the AAP wave in Gujarat," Sisodia tweeted.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NEW DELHI
MONDAY
OCTOBER 10, 2022

NAME OF NEWSPAPERS---------- ----DATED----------

Hindustan Times

Fixing basic infra key to achieve 24/7 Capital city

Risha Chitlangia
risha.chitlangia@hindustantimes.com

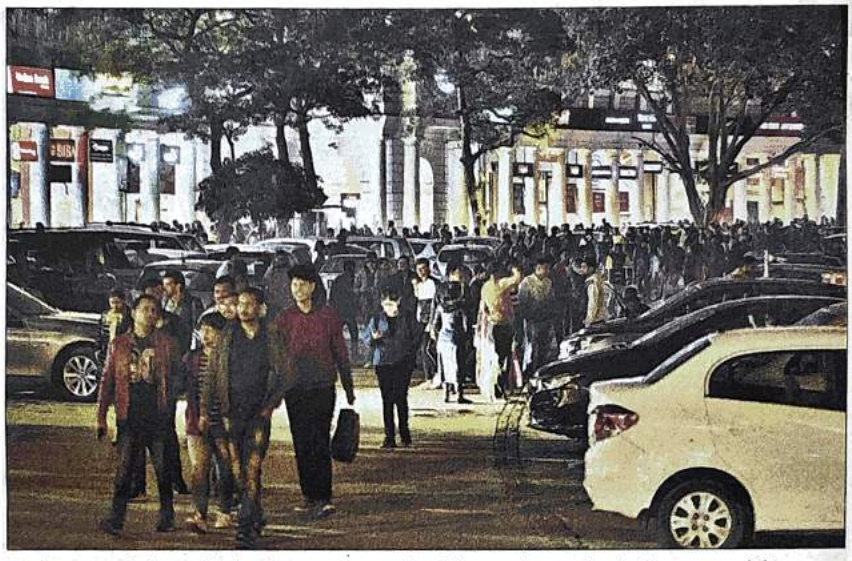

Traders associations said that the government should ensure law and order in commercial areas where establishments will be allowed to open 24 hours. HT ARCHIVE

NEW DELHI: Delhi lieutenant governor VK Saxena's decision to allow restaurants, chemist shops, and transport services to operate round-the-clock is a first step towards making Delhi a 24-hour city, a concept first introduced in the draft Master Plan of Delhi-2041 last year.

However, experts feel that to ensure a vibrant nightlife and a thriving night time economy, some quick measures have to be taken to ensure public safety, especially for women, modify timings for availability of public transport.

The Delhi government is likely to issue a notification regarding exceptions in the Delhi Shops and Establishment Act, 1954, in a week's time. The move will immediately benefit 300 plus establishments ranging from hotels, restaurants, eateries to online delivery services of food, medicines, logistics and other essential commodities, transport and travel services that have been such approvals for the past six years.

Both the Aam Aadmi Party government and the Delhi development Authority (DDA) have been pushing for night time economy.

The draft MPD-2041, which will be finalised by April next year, has proposed development of nightlife circuits around cultural precincts, heritage areas, central business districts to provide the city a "vibrant nightlife". It proposed that restaurants and commercial establishments remain open 24x7 so that Delhi can become a "24-hour city" just like London, Paris, New York and Amsterdam.

While the business community, civic society members and experts have welcomed the decision, they said a host of measures are needed to implement the idea.

Public transport

A good public transport system during night and well-planned spaces are essential for the city to have a nightlife. London, New York, Seoul, Barcelona, Hong Kong, and Tokyo are some cities where public transport is available 24x7.

Currently, the Metro services are not available after 11 -11.30 pm, the frequency of buses drops significantly after 10pm, and a limited number of auto-rickshaws ply at night.

Anumita Roychowdhury, executive director, research and advocacy at Centre for Science and Environment said it is a good move to promote night time economy and nightlife in the city, but there is a need to ensure safe access to public transport.

She said, "To promote night time economy, it is important to provide people safe access and good public transport services. Otherwise what will happen is that it will only get people who have a personal vehicle. The purpose of the night time economy will not be fully optimized unless we give good public transport service and also good placemaking."

Hitesh Vaidya, director, National Institute of Urban Affairs (which has helped DDA in preparing the Master Plan vision document), said, "Cities should consciously support night time economies and active nightlife. This has several potential positives. It will support numerous activities that can thrive at night, for instance, cultural activities, certain industries, logistics, etc. thereby helping to stagger work timings and reduce congestion on roads. This will also substantially increase productive use of city resources by utilising city infrastructure throughout the day, resulting in higher economic output."

Public safety

Safety of people, specially women, experts say has to be ensured during night time. It is not just public transport, but measures have to be taken to ensure that women feel safe to go out at night.

Kalpana Viswanath, co-founder and CEO of Safetipin, said, "There is a need to address issues related to the safety of women so that they can work at night and visit these nightlife hubs. Good public transport system, specially last mile connectivity, is essential and there is also a need to have more eyes on the street. Cities like Bangkok have a good nightlife and women feel safe to go out. They should also allow street vendors to do business at night, as they act as eyes on the streets."

Markets and restaurants

Welcoming the decision, restaurant owners said that this has been a longstanding demand, and market associations said that the government should allow all commercial establishments to open round-the-clock.

Manpreet Singh, the owner of Zen restaurant in Connaught Place and the treasurer of National Restaurant Association of India (NRAI), said, "This has been our long pending demand that markets like Connaught Place should be allowed to operate 24x7. This will not only provide more employment opportunities, but also generate revenue for the government. We are hopeful that the decision to serve liquor will also be extended after this decision."

Traders association said that the government should ensure law and order in commercial areas where establishments will be allowed to open 24 hours. Atul Bhargava, president of New Delhi Traders Association at Connaught Place, said, "It is a popular concept abroad and can be done here too, but the police have to ensure law and order. The government should first try it on a pilot basis in a few commercial centres."

But traders in Lajpat Nagar say that all city markets should be allowed to remain open at night. Ashwani Marwah, general secretary, traders Association Lajpat Nagar said, "At present, there is massive rush during weekends, as people don't get time to visit the markets during weekdays due to their working hours. Most markets close by 8-9 pm. All markets should be allowed to open round-the-clock. Market associations can be roped for security."

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---- THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI MONDAY, OCTOBER 10, 2022 ----DATED----

To give city sporting chance, DDA to closely track work at complex

Sidhartha.Roy@timesgroup.com

New Delhi: Last month, the foundation for Delhi Development Authority's (DDA) first sports complex to be built under Public-Private Partnership (PPP) was laid by lieutenant governor VK Saxena at Dwarka sector 19-B. The land development agency is now planning to engage a consulting engineering firm for daily monitoring of the construction of this first-of-its-kind project.

The 'Integrated Multi-Sports Arena' is coming up on a site spread over around 51 acre and will boast of an international cricket-cum-football stadium with a minimum seating capacity of 30,000, indoor multi-sports facilities with 2,000 seating capacity, a membership-based sports club with capacity to accommodate 3,000 members.

The Rs 350 crore project will also include facilities for tennis, badminton, squash, table tennis, swimming pool etc. According to DDA officials, all sports facilities developed on the site will also be available for users on pay and play basis for a minimum of 25% of their capacity, without requiring membership of the sports club.

The area of the sports facility is going to be 6.4 lakh square feet, apart from 3.45 lakh square feet of commercial facilities . The project is being taken up by Omaxe through PPP mode on design, finance, operate and transfer model with a concession period of 30 years. The facility is expected to be completed within three years.

Apart from sports facilities, the arena will also provide commercial facilities, including retail, hotel, hospitality, commercial office space and supporting facilities for sports.

> **According to DDA officials, all sports facilities developed on the site will also be available for users on pay and play basis for a minimum of 25% of their capacity, without requiring membership of the sports club**

For the sports facility, the role and functions of the 'independent engineer' to be brought on board will be to review, inspect, and monitor construction works for the project facilities. The firm will also conduct tests on completion of construction and issue completion or provisional certificate.

During the construction period, the independent engineer will undertake a detailed review of the drawings and detailed project report to be furnished by the concessionaire, along with supporting data, including geo-technical and hydrological investigations, characteristics of materials from borrow areas and quarry sites and topographical surveys. The independent engineer will complete the review and send comments and observations to DDA.

Inspection of the construction works and the project facilities will be carried out once every month and an inspection report giving overview of the status, progress, quality and safety of construction, including the work methodology adopted, the materials used and their sources, and conformity of construction works, etc will be submitted.

Apart from Dwarka, DDA is also working on one sports complex each at Rohini and Narela under a similar PPP model. An official said that the plot identified at Rohini Sector-34 measures approximately 53.6 acres and the tentative project cost is estimated at Rs 150 crore. The plot at Narela Sector- A7 is much smaller at 18 acres and the project cost is estimated to be around Rs 57 crore.

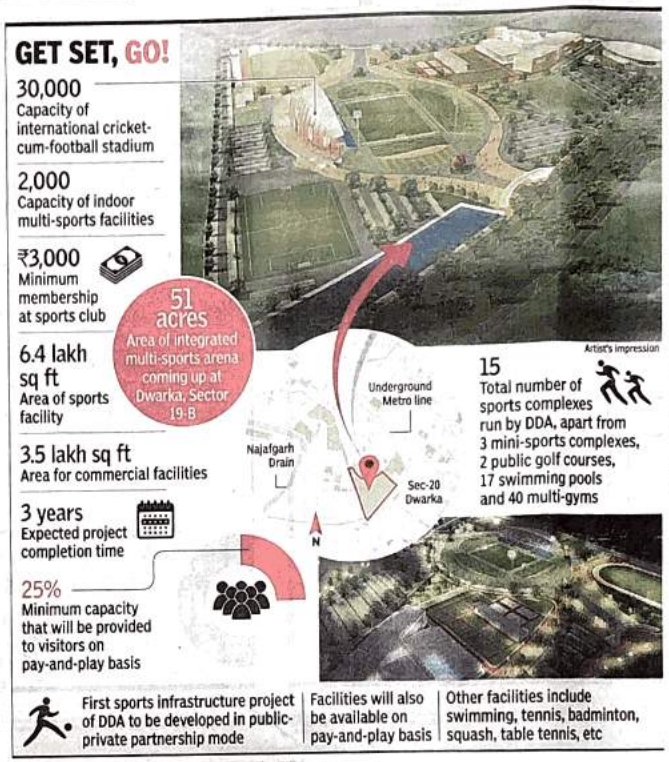

Conversion tax: AAP, MCD spar over 'change' in payment system

New Delhi: The Aam Aadmi Party on Sunday alleged that the Municipal Corporation of Delhi had changed the payment system of conversion tax without consulting traders.

"The BJP-led MCD has waged a war against the people of Delhi and especially against the businessmen of Delhi. MCD officers have been threatening the traders of Delhi since last week. Notices are being sent to them, threatening to seal their shops" said AAP MCD in-charge Durgesh Pathak.

MCD rejected the allegations as "fake".

An MCD official said: "The corporation finds such claim malicious and denounces it downright. There is no retrospective effect of the revised rate. The revised charges are to be paid with the date of its coming into effect in 2018. Further, the amendment in rates, as notified by DDA, is not a new tax, but a mere revision. Moreover, it was not a backdoor entry, but came into existence vide a public notification."

According to AAP In 2011, MCD had said that traders would need to pay conversion tax for commercial activities in industrial areas. Traders were asked to pay tax either at one go at Rs 8,000 per square metre or in instalments at Rs 1,000 per square metre for 10-15 years. Majority of traders chose the instalment method and they were paying these at the year end. "Their instalments were about to end in 2020, but BJP ordered them to pay Rs 21,000, instead of Rs 8,000 per square metre for the entire plot," Pathak alleged. TNN

Hindustan Times NEW DELHI MONDAY OCTOBER 10, 2022

Dwarka sports complex: Development agency invites bids for engg consultant

HT Correspondent
htreporters@hindustantimes.com

NEW DELHI: The Delhi Development Authority (DDA) has invited bids to appoint an independent engineering consultant for its first integrated sport complex project in Dwarka that will be implemented on the Public Private Partnership (PPP) model. The land-owning agency has also invited bids to develop similar facilities in Narela and Rohini.

In August, the DDA awarded the work for the construction of the facility, that will include a cricket-cum-football stadium along with indoor sports facilities and commercial development to Omaxe Limited. Last month, lieutenant governor VK Saxena laid the foundation stone for the project, which officials said will be the Capital's biggest sport facility in Delhi.

Spread over 51 acres, the state-of-the-art sports facility will be developed and managed by Omaxe limited for 30 years. The ₹350 crore project, under which sport facilities will occupy an area of 6.4 lakh sqft, will be completed within three years. The area will also have commercial facilities, including retail, hotel, hospitality, commercial and office space. Supporting facilities for sports will be provided for 99 years' lease on the design, finance, operate and transfer model.

According to the tender document, an independent engineering firm will review the construction plan and monitor the work. "The role of the firm will be to review the drawing and documents. It will also inspect and monitor the construction works, conduct tests and issue completion/provisional certificate," the tender document said. The land-owning agency plans to develop similar state-of-the-art sports facilities at Rohini and Narela, for which it has requested for a consultant. According to a senior DDA official, the two projects will close around ₹207 crore. According to the tender document, the consultant will have to "study and prepare current state scenario, user surveys, demand surveys, growth and demand assessment".

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

दैनिक जागरण
नई दिल्ली,
10 अक्टूबर, 2022

NAME OF NEWSPAPERS---------- DATED----------

रिमझिम में भी सड़कें लबालब, फंसे वाहन

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : लगातार तीन दिनों से हो रही वर्षा से लोगों की परेशानी बढ़ रही है। राजधानी में जलभराव से जगह-जगह जाम लग रहा है। इससे वाहन चालकों का काफी समय खराब हो रहा है। तीसरे दिन दिल्ली में रिमझिम वर्षा से भी दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। सर्वाधिक खराब स्थिति दक्षिणी और पूर्वी दिल्ली के इलाकों की रही। कई सड़कों पर जलभराव के चलते लोगों को काफी समय तक जाम से जूझना पड़ा। दक्षिणी दिल्ली में नाले-नालियों की सफाई न होने कारण संगम विहार, देवली, खानपुर, जैतुपर, मीठापुर, हरि नगर, फतेहपुरबेरी, चांदनहुला, असोला व छतरपुर इलाकों में सड़क पर भरे पानी के कारण लोगों का अपने घर से निकलना दुश्वार हो गया। संगम विहार में तो सड़क का पानी लोगों के घरों के अंदर भी पहुंच रहा है। जबकि छतरपुर इलाके में पानी के कारण बाइक सवार लोग अक्सर सड़क पर गिर रहे हैं। मोलड़बंद के स्कूल रोड, टंकी रोड आदि पर भरा पानी लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है।

यातायात पुलिस के अनुसार दिल्ली में 13 स्थानों पर जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। इसमें मध्य दिल्ली का अशोका रोड और पंचकुइंया पर भी जलभराव हो गया। दिल्ली के अन्य स्थान जैसे रोहतक रोड, मथुरा रोड, आउटर रिंग रोड, एनएच-48, में शिवमूर्ति मार्ग के पास जलभराव हुआ। इसी प्रकार धौलाकुंआ, जीटी करनाल रोड डिपो, धौलाकुंआ फ्लाईओवर मोती बाग के पास जलभराव हुआ। जबकि निगम की रिपोर्ट के अनुसार तीन शिकायतें जलभराव को लेकर कंट्रोल रूम में आईं। इसमें बेगमपुर बरवाला

जैतपुर इलाके के हरि नगर में सड़क पर भरा पानी● फोटो- स्थानीय निवासी

रोड की एक शिकायत है जबकि मुबारक पुर रोड पर जलभराव की दो शिकायतें हैं। 11 शिकायतें पेड़ व उनके हिस्से गिरने की आईं। जिसमें मानसरीवर गार्डन जी ब्लाक, 34 ब्लाक त्रिलोकपुरी, दक्षिणपुरी, फोर्टिस अस्पताल शालीमार बाग, आंबेडकर पार्क शाहदरा, सफदरजंग एन्क्लेव, कारगिल अपार्टमेंट, एलआइजी फ्लैट वसंतकुंज, सरकारी स्कूल हरि नगर, जहांगीरपुरी, डीडीए फ्लैट मुनिरका के इलाके शामिल हैं।

पूर्वी दिल्ली में यहां हुआ जलभराव: यमुनापार में लगातार तीन दिन से हो रही वर्षा की वजह से झिलमिल अंडरपास, अप्सरा बार्डर अंडरपास, स्वामी दयानंद मार्ग पर ईस्ट आजाद नगर, पांडव नगर, मंडावली, वजीराबाद रोड के पास की सड़कों पर जलभराव के चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि छुट्टी का दिन होने के कारण सड़कों पर जाम की स्थिति कम रही। झिलमिल अंडरपास में जलभराव के चलते गाड़ी, छोटे व्यवसायी वाहन व दोपहिया वाहनों के इंजन में पानी भरने से वह खराब होकर बीच में ही बंद पड़ गए। अपने वाहनों को निकालने के लिए लोगों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी।

छतरपुर में पानी के कारण हो रही परेशानी

छतरपुर इलाके में सुल्तानपुर रोड, आया नगर, अंबेडकर कालोनी, असोला आदि इलाकों में पानी भरा होने के कारण लोगों को काफी परेशानी हुई। फतेहपुरबेरी से लेकर चांदनहुला तक करीब डेढ़ किलोमीटर तक पानी भरा होने से राहगीरों को आने-जाने में काफी मुश्किल हुई। शनिवार सुबह से ही हो रही वर्षा के कारण लोग घर से नहीं निकल पाए। स्थानीय निवासी रिषिपाल महाशय ने बताया कि टूटी सड़कों पर चलते हुए अक्सर बाइक सवार गिरकर घायल हो जाते हैं। नालियों की सफाई न होने के कारण वे चोक हो गई हैं जिससे वर्षा का पानी निकल नहीं पाता है और वह सड़क पर ही भरा रहता है। इससे वर्षा के कारण मार्ग ठप हो जाता है। शिकायत के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो पाया है।

संगम विहार में घरों में भरा पानी

दिन भर हुई वर्षा के कारण संगम विहार व देवली इलाके में गलियों में पानी भर जाने से लोग परेशान हुए। जिन लोगों के घर सड़क के लेवल से नीचे हैं उनमें पानी भर गया। सड़क पर भरे पानी के कारण लोगों का गली में निकलना दुश्वार है। स्थानीय निवासी रजनीश प्रजापति ने बताया कि समस्या के समाधान के लिए स्थानीय विधायक से लेकर निगम के अधिकारियों तक से शिकायत की गई, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। हर साल बरसात के मौसम में यही हाल होता है, लेकिन अफसरों पर जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है।

एक नजर में

सीवर कर्मियों के मामले में कांग्रेस ने किया हाई कोर्ट के आदेश का स्वागत

नई दिल्ली : कांग्रेस ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें मुंडका की सीवर लाइन में ड्यूटी के दौरान दो कर्मियों की मौत हो गई थी। कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लेकर स्वजन को 10-10 लाख रुपये का मुआवजा व अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने का आदेश जारी किया है। डीडीए को 30 दिनों में मुआवजा और अनुकंपा पर नौकरी देने के आदेश दिए हैं। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता डा. नरेश कुमार ने प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी का भी धन्यवाद ज्ञापित किया क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया था। (वि)

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWS हिन्दुस्तान सोमवार, 10 अक्तूबर 2022 04

अदालत से | रोहिणी रिहायशी योजना में चार लाख रुपये मुआवजा बढ़ाने के फैसले का लाभ करीब एक हजार से अधिक किसानों को होगा

17 साल पहले अधिगृहित जमीन पर मुआवजा बढ़ाया

■ हेमलता कौशिक

नई दिल्ली। रोहिणी रिहायशी योजना (रेजिडेंसियल स्कीम) के लिए 17 साल पहले अधिगृहित जमीन पर अदालत ने चार लाख रुपये मुआवजा बढ़ाने के आदेश दिए हैं। अदालत ने दिल्ली विकास प्राधिकरण को कहा कि बढ़ी मुआवजा रकम का भुगतान तय ब्याज समेत वादी को किया जाए। अदालत के इस आदेश का लाभ एक हजार से ज्यादा किसानों को होगा।

रोहिणी स्थित अतिरिक्त जिला न्यायाधीश दीपक डबास की अदालत ने माना कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने किसान की जमीन की उचित कीमत नहीं लगाई थी। इसलिए अब डीडीए खेती की जमीन पर चार लाख दस हजार 750 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से अतिरिक्त मुआवजा रकम का भुगतान करे।

अदालत ने सुनवाई के दौरान पाया कि जमीन अधिगृहित करते समय प्रति एकड़ के हिसाब से 15 लाख 70 हजार रुपये मुआवजा दिया गया था। जबकि उक्त जमीन का बाजार मूल्य बहुत अधिक था। इसी को ध्यान में रखते हुए मुआवजा रकम बढ़ाई गई है। अब प्रति एकड़ 19 लाख 80 हजार 750 रुपये के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा।

जमीन की उर्वरता का दिया हवाला

याचिका में कहा गया कि उनकी जमीन की उर्वरता क्षमता बेहतरीन थी। अच्छी फसल उग रही थी। शहरी गांव होने के कारण आस-पास के क्षेत्र विकासशील थे। इस समय अगर जमीन उनके कब्जे में होती तो कीमत बहुत ज्यादा होती। यह जमीन राष्ट्रीय राजमार्ग और औद्योगिक क्षेत्र के नजदीक थी। कुछ दूरी पर ही कॉलोनी बन रही थीं। ऐसे में उनकी जमीन का मूल्य बेहद कम आंका गया। अदालत ने इस बाबत तमाम पक्ष सुनने के बाद मुआवजा बढ़ाने के निर्देश दिए। अदालत ने कहा कि बढ़ी मुआवजा रकम पर डीडीए प्रति साल के हिसाब से 9 फीसदी का ब्याज का भुगतान करेगा। वहीं, मुआवजा रकम पर 30 फीसदी हर्जाना रकम का भुगतान भी डीडीए को वादी किसान परिवार को करना होगा।

6,130 बीघा जमीन की गई थी अधिगृहित : डीडीए ने वर्ष 2005 में बरवाला गांव के किसानों की खेती की छह हजार 130 बीघा जमीन अधिगृहित की थी। इस जमीन को रोहिणी रेजिडेंसियल स्कीम के लिए अधिगृहित किया गया था। इन फ्लैटों का आवंटन हुए भी सात साल हो गए हैं। 17 साल बाद अदालत ने एक किसान (जिसकी मृत्यु हो चुकी है) की पत्नी की याचिका पर यह फैसला सुनाया है।

अदालत ने कहा कि संबंधित जमीन का बाजार मूल्य कम आंका गया। किसानों का इसी हिसाब से कम मुआवजा मिला। जबकि यह उनकी खेती की जमीन थी। अदालत ने कहा कि किसानों की जमीन उनकी आय का साधन होता है। ऐसे में कम मुआवजा देना न्यायसंगत नहीं होगा।

डीडीए जलाशयों का पुनर्निर्माण करेगा

■ सज्जन चौधरी

नई दिल्ली। दिल्ली को झीलों का शहर बनाने की योजना फिलहाल अधर में लटक गई है। दिल्ली जल बोर्ड ने 500 से अधिक जलाशयों को दिल्ली विकास प्राधिकरण को वापस करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। माना जा रहा है अब डीडीए खुद इन जलाशयों के पुनर्निर्माण का कार्य करेगा।

डीडीए अधिकारियों का कहना है कि इन जलाशयों के सौंदर्यीकरण और पानी से जुड़े कार्य किए जाने के लिए डीडीए की ओर से अनापत्ति पत्र भी दिया जा चुका था। अधिकारियों का मानना है कि दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच चल रहे विवाद के चलते दिल्ली जल बोर्ड ने इन जलाशयों को वापस किया है। गौरतलब है दिल्ली जल बोर्ड के मुखिया मुख्यमंत्री और डीडीए के मुखिया उपराज्यपाल होते हैं। जल निकायों से जुड़े डीडीए के अधिकारियों ने बताया कि हमने जल बोर्ड के अनुरोध पर एनओसी जारी किया था। लेकिन, अब उन्होंने इसे वापस करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। डीडीए अधिकारियों ने बताया कि कई जलाशयों पर काम शुरू भी नहीं हुआ है। कई जगह टेंडर मांगे गए, लेकिन आवंटन नहीं किया गया।

जल बोर्ड की ओर से वापस किया गया कार्य

इन जल निकायों पर किए जाने वाले कार्य के दो मुख्य हिस्से थे। पहला, जल निकाय में स्वच्छ जलापूर्ति सुनिश्चित करना और दूसरा स्थान को साफ करना। दिल्ली जल बोर्ड शुरू में भूनिर्माण सहित सभी काम खुद करने की योजना बना रहा था। अब, सारा काम डीडीए को करना होगा। अधिकारियों ने बताया कि जो काम जल बोर्ड के दायरे में आता है, वह है भलस्वा झील के पास एक इंटरसेप्टिंग ड्रेन बनाना। लेकिन इसका पूरा काम (तालाब की सफाई और भूनिर्माण) अब डीडीए को करना होगा। गौरतलब है दिल्ली में अधिकांश जल निकायों का मालिकाना हक डीडीए के पास है और जल बोर्ड की ओर से इन्हें वापस उनके पास भेज दिया गया है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

THE INDIAN EXPRESS, MONDAY, OCTOBER 10, 2022 ----------DATED----------

Over 300 businesses can now operate 24x7 after L-G nod

EXPRESS NEWS SERVICE
NEW DELHI, OCTOBER 9

FROM RESTAURANTS to transport services and BPOs to online delivery services, all those who apply for exemptions will be allowed to operate 24×7 in Delhi starting next week, with L-G V K Saxena approving the proposal to exempt 314 such places to operate all day long, some of them pending since 2016, officials said.

"The L-G has directed that notification to this effect be issued in 7 days. The decision of providing exemption under Sections 14, 15 & 16 of the Delhi Shops & Establishment Act, 1954, is expected to boost employment generation and promote a positive and favourable business environment that is a pre-requisite for economic growth. The decision will also provide a fillip to the much desired 'nightlife' in the city," said an official.

These establishments can apply online to get these exemptions.

Section 14 of the original Act said women or young cannot be asked to work between 9 pm and 7 am in Delhi. According to Section 15, the government had the right to fix opening and closing times for establishments. In a 1979 notification, this was set at 9 am to 7 pm. Section 16 mandates establishments to remain closed one day per week.

In 2004, changes were made to the Act and the opening time was extended to 11 pm. This, however, was not mandatory. The mandate for shops to remain closed one day per week was also relaxed. "Exemptions under Sections 14, 15 & 16 of the said Act enables commercial establishments to operate on a 24X7 basis, subject to certain conditions that entail welfare of labour and security etc," said the official.

Both the Delhi government as well as the DDA Masterplan have advocated for a "24x7 Delhi" over the past five years.

According to L-G office officials, establishments have been sending applications for exemptions to be made but the Labour Department had not been dealing with them fairly. "Approving the proposal, the L-G took a very serious view of and flagged issues of inordinate delay, adhocism, randomness and unjustified discretion on part of the Labour Department in disposing applications made by establishments for these exemptions. It may be noted out of the total 346 pending applications, 18 from 2016, 26 from 2017, 83 from 2018, 25 from 2019, 4 from 2020 and 74 applications from 2021 had not been processed by Labour Department on time," added the official.

"These applications were kept pending for no reason even as just 2 applications, one of 2017 and another of 2021 were processed and sent for approval, in a display of unexplained discretion on part of the Labour Department, which strongly indicated prevalence of corrupt practices. This shows a complete unprofessional attitude and lack of due diligence on part of the Labour Department and amounted to the Department having adopted a 'pick and choose policy' in processing such applications. Further, inordinately delayed processing of such routine applications also negatively affects confidence/ sentiments of the business community."

Officials added it was only after the L-G office prodded it that the Labour Department put in place a digital mechanism for receipt of applications. The L-G has strictly advised that such applications are disposed of within a prescribed timeline so a conducive investor-friendly business environment and positive confidence could be instilled in entrepreneurs and businesses.

He has also directed the Labour Department to ensure such delays do not occur in future, a mechanism is developed for transparent and effective monitoring, reasons for pendency be ascertained, responsibility is fixed and suitable action taken against erring officials.

When contacted, the government did not respond to calls and messages seeking comment.

दैनिक जागरण नई दिल्ली, 10 अक्टूबर, 2022

कन्वर्जन चार्ज को लेकर लगाए गए सभी आरोप झूठे : निगम

जासं नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम ने आम आदमी पार्टी (आप) के उन आरोपों का खंडन किया है जिसमें औद्योगिक क्षेत्रों में कन्वर्जन चार्ज वसूलने का आरोप लगाया गया। निगम ने कहा कि आरोप पूरी तरह से झूठे हैं। निगम के प्रेस और सूचना निदेशालय की ओर से जारी बयान मे कहा गया है कि कन्वर्जन चार्ज की दर दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने 2009 में अधिसूचित की थी। क्षेत्रवार निर्धारित दरों के आधार पर कन्वर्जन चार्ज लिया जा रहा है। निगम ने कहा कि कन्वर्जन चार्ज की दर कभी भी एक हजार रुपये प्रति वर्गमीटर नहीं थी, जैसा कि दावा किया जा रहा है। निगम ऐसे सभी आरोपों को दुर्भावनापूर्ण मानते हुए सिरे से नकारता है। पुनः निर्धारित दरों को पूर्व प्रभावी आधार पर लागू नहीं किया गया है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

the pioneer
I MONDAY I OCTOBER 10, 2022
DATED

MCD threatening to seal shops in name of conversion tax: AAP

STAFF REPORTER ■ NEW DELHI

The AAP on Sunday alleged that MCD is threatening to seal shops across the national Capital in name of conversion tax by sending notices to traders and unnecessarily harassing the businessmen. AAP MLA Durgesh Pathak said MCD changed the payment system of conversion tax without consulting the businessmen of Delhi and hiked the taxed rate arbitrarily.

"BJP-ruled MCD has waged a war against the people of Delhi and especially against the businessmen of Delhi. BJP leaders and MCD officers have been threatening the traders of Delhi since last week. Notices are being sent to them, threatening to seal their shops," said Pathak.

"In 2010, BJP-ruled MCD came up with a new rule that whoever is doing commercial activities in the industrial area will have to pay a tax in the form of conversion tax. Most of the traders had adopted the 10-15 year installment formula because they were small traders and they did not have a huge income. Everyone used to submit their conversion rate whenever on time at the end of the year," said Pathak.

"This rule started in 2010 and came into force in 2011. It was supposed to run till 2020-2021 since people had opted for the 10 years formula. But in 2018, MCD came up with a new rule through a backdoor entry. They said that from now on, instead of paying Rs 8 thousand per sq mtr, they will have to pay ₹21 thousand per sq mtr and that too for the entire plot," said Pathak.

"Now, since the past one week, BJP leaders and MCD officials are calling each and every businessman. Those who were supposed to pay ₹10 lakh are now given notices of ₹1 crore to ₹2 crore. They have been ordered to deposit this money within 15 days failing which their shops will be sealed.

Allegation baseless: MCD

PNS ■ NEW DELHI

Speaking on the issue, a senior MCD official said the corporation has come to notice that a new fake allegation has been made against the civic body regarding conversion charges levied by the MCD in industrial area.

"It has been claimed in the allegation that traders were asked to pay conversion tax either in one go at ₹8000 per sq metre or in installments at ₹1000 per sq metre for 10-15 years. The Corporation would like to make it clear that this is not true in facts," he said.

"The rates for use conversion charges from industrial to commercial were notified by DDA on the basis of built-up area per sq metre.

The rate fixed for Central, South and Dwarka area was ₹12,508/- per sq metre of built up area while that of North, East, West and Rohini was ₹8,097/- per sq metre of built up area and Narela at ₹1300 per sq metre," he said.

"Later on DDA revised the rates for use conversion charges from Industrial to commercial based on plot area basis and the rates were decided Industrial Estate wise. The revised rate for nine Industrial Estates of Delhi as notified by DDA varies from ₹30,971 per sq metre to ₹17,910 per sq metre across these industrial estates," MCD official said.

"The use conversion charges were never ₹1000/- per sq. metre any time in the past as claimed. The Corporations finds such claim malicious .

There is no retrospective effect of the revised rate. The revised charges are to be paid with the date of its coming into effect in 2018," MCD official added.

राष्ट्रीय सहारा
8 अक्टूबर • 2022

आईआरएस अमित निगम पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का केस

लखनऊ (एसएनबी)। लखनऊ और मुरादाबाद में आयकर विभाग में तमाम अहम पदों पर तैनात रहे आईआरएस अधिकारी अमित निगम के खिलाफ सीबीआई, गाजियाबाद की एंटी करप्शन ब्रांच ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का केस दर्ज किया है। सीबीआई ने अमित निगम के खिलाफ दर्ज एफआईआर में उनकी कुल आय से 7.52 करोड़ रूपये से अधिक की चल-अचल संपत्तियों को खरीदने का जिक्र किया है। सीबीआई की प्रारंभिक जांच में उनकी लखनऊ में चार और दिल्ली में एक बेशकीमती संपत्तियों का भी पता चला है जिनमें से लखनऊ की आम्रपाली योजना में स्थित एक संपत्ति की कीमत 4.24 करोड़ रूपये आंकी गयी है।

एफआईआर के मुताबिक अमित निगम की जनवरी 2008 से जून 2018 के बीच की कुल आय और व्यय की पड़ताल सीबीआई द्वारा की गयी थी जिसमे सामने आया है कि इस अवधि में उन्होंने अपनी आय से 7.52 करोड़ रूपये से अधिक की संपत्तियां जुटाई। इसमें दिल्ली की जहांगीरपुरी स्थित डीडीए से खरीदा गया मकान, लखनऊ की जानकीपुरम योजना में प्लॉट, आम्रपाली योजना में निर्मित किया गया आलीशान मकान और इंदिरानगर में दो प्लॉट शामिल हैं। सीबीआई ने जब उनसे इस बारे में पूछताछ की तो उन्होंने आय और व्यय के इस अंतर को लेकर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया।